Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of May, 2024.

On 07.05.2024, Union Home secretary met Mr. Thierry Mathou, Ambassador of France to India.

2. On 23.05.2024 the High-Level Committee (HLC) approved the proposals of 04 States viz. Andhra Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Telangana for Expansion and Modernization of Fire Services, from the earmarked allocated fund under 'Preparedness and Capacity Building' funding window of NDRF.

3. During the month, Union Home secretary held meetings to review the ground subsidence in village Pernote - A, Ramban District, Jammu & Kashmir, the forest fire incidents in Uttarakhand and for finalization of the Policy on "Resettlement of people affected by coastal and river erosion under National Disaster Response Fund (NDRF).

4. 4th Joint Security Committee Meeting between India and UAE was held on 08.05.2024 at New Delhi. The Indian Delegation was led by Additional Secretary, MHA, Shri Piyush Goyal and the UAE delegation was led by the Under Secretary of the Ministry of Interior, His Excellency Staff Major General Khalifa Hareb Al Khaili.

5. Vide MHA's Notifications dated 20.05.2024 and 24.05.2024, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunals have confirmed the ban on following insurgent groups of North Eastern States under Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967:-

(i) National Liberation Front of Tripura (NLFT) & All Tripura Tiger Force (ATTF) of Tripura as 'Unlawful Association' for a period of five years w.e.f. 03.10.2023.

(ii) 7 Meitei Extremist Organisations of Manipur as Unlawful Association' for a period of five years w.e.f. 13.11.2023.

6. On 11.05.2024, one Advisory issued to State Governments to sensitize them with respect to possible LWE threats during elections.

7. On 10.05.2024 a meeting of Central Level Committee (CLC) was held under the Additional Secretary (LWE) with the Nodal Officers & Officers from State Home Department of LWE affected States Chhattisgarh, Jharkhand & Odisha under Special Central Assistance (SCA) for most LWE -affected districts to review the progress & challenges of Project Entry in the SCA Portal for physical & financial progress.

8. A meeting of the Joint Monitoring Committee (JMC) was held under the Additional Secretary (NE), MHA on 29.05.2024 to review the status of implementation of Bodo Accord (2020), Karbi Accord (2021), Adivasi Accord (2022), DNLA Accord (2023) and ULFA Accord (2023).

*****

गृह मंत्रालय - मई, 2024 की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय घटनाक्रम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम।

दिनांक 07.05.2024 को केंद्रीय गृह सचिव ने भारत में फ्रांस के राजदूत श्री थिएरी माथौ से मुलाकात की।

2. उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने दिनांक 23.05.2024 को एनडीआरएफ की 'तैयारी और क्षमता निर्माण' फंडिंग विंडो के अंतर्गत निर्धारित आबंटित निधि से 04 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया।

3. इस माह के दौरान, केंद्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के पेरनोट-ए गांव में भू-स्खलन, उत्तराखंड में दावानल की घटनाओं की समीक्षा करने तथा तटीय और नदी कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास संबंधी नीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कीं।

4. भारत और यूएई के बीच संयुक्त सुरक्षा समिति की चौथी बैठक दिनांक 08.05.2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के अपर सचिव, श्री पीयूष गोयल ने किया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंडर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, हिज एक्सीलेंसी स्टाफ मेजर जनरल खलीफा हरेब अल खैली ने किया।

5. गृह मंत्रालय की दिनांक 20.05.2024 और 24.05.2024 की अधिसूचनाओं के तहत, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरणों ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध की पुष्टि की है: -

(i) नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को दिनांक 03.10.2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में प्रतिबंधित किया गया।

(ii) मणिपुर के 7 मैतेई उग्रवादी संगठनों को दिनांक 13.11.2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया।

6. राज्य सरकारों को चुनावों के दौरान संभावित वामपंथी उग्रवाद संबंधी खतरों के बारे में अवगत कराने के लिए दिनांक 11.05.2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई।

7. वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए एससीए पोर्टल में परियोजना प्रविष्टि की प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 10.05.2024 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अधिकतर जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के गृह विभाग के नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में केंद्र स्तरीय समिति (सीएलसी) की बैठक आयोजित की गई।

8. बोडो समझौता (2020), कार्बी समझौता (2021), आदिवासी समझौता (2022), डीएनएलए समझौता (2023) और उल्फा समझौता (2023) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए दिनांक 29.05.2024 को अपर सचिव (एनई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) की बैठक आयोजित की गई।

*****